नव भारत
1934 से

5 भागवत-योगी की बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन

6 अब सुधरेगा बांग्लादेश का रवैया ?

7 सस्ती एआई से इंटेलिजेंस एरा की शुरुआत

8 ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने भारत को 19 रनों से हराया

एआई का उपयोग अवसर में बदलें

हम साथ मिलकर ऐसा रोडमैप बनाएं जिससे एआई का सही प्रभाव दिखे : मोदी

नयी दिल्ली 19 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को समूची मानवता की भलाई के लिए साझा संसाधन करार देते हुए कहा है कि सभी को मिलकर इसे मानवता के लिए सबसे बड़े अवसर के रूप में बदलने की दिशा में काम करना होगा. मोदी ने गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के उद्घाटन के बाद वैश्विक नेताओं के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि यह सम्मेलन मानव केन्द्रीत और संवेदनशील एआई इकोसिस्टम के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा.

उन्होंने इसे एक बड़ा अवसर करार देते हुए इसका भरपूर फायदा उठाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा, ' हम इतिहास पर नजर डालें, तो पता चलता है कि इंसान ने हर बाधा को एक नए अवसर में बदला है. आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है. हमें मिलकर इस बाधा को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है.' प्रधानमंत्री ने कहा कि सही समझ से ही सही परिणाम मिलते हैं इसलिए जरूरी है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोडमैप बनाएं जिससे एआई का सही प्रभाव दिखे, और सही प्रभाव तभी होता है, जब हम सही समय पर सही नियत से, सही निर्णय लेते हैं.

श्री मोदी ने कहा कि एआई को लेकर भारत की दिशा स्पष्ट है, भारत का विचार स्पष्ट है. एआई पूरी मानवता की भलाई के लिए एक साझा संसाधन है. उन्होंने कहा, ' हमें मिलकर ऐसा एआई भविष्य बनाना होगा, जो नवाचार को आगे बढ़ाएं, समावेशन को मजबूत करे और मानव मूल्यों का समावेश करके आगे बढ़े. जब प्रौद्योगिकी और मानव विश्वास साथ-साथ चलेंगे, तो एआई का सही प्रभाव दुनिया पर दिखेगा.' उन्होंने कहा कि एआई की वैश्विक यात्रा में आकांक्षी भारत की बड़ी भूमिका है, और अपने इस दायित्व को समझते हुए भारत आज बड़े कदम उठा रहा है. भारत के एआई मिशन के माध्यम से आज देश में 38,000 जीपीयू हैं, और अगले 6 महीनों में हम 24,000 जीपीयू और लगाने जा रहे हैं.

भारत एआई और डिजिटल क्रांति का नया वैश्विक चेहरा

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत की डिजिटल प्रगति और प्रौद्योगिकी नेतृत्व की जमकर तारीफ की. अपने संबोधन की शुरुआत 'नमस्ते' और अंत 'जय हो' के साथ करते हुए मैक्रों ने भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और समावेशी तकनीकी विकास को वैश्विक मानक बताया. मैक्रों ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि 10 साल पहले उसके पास न बैंक खाता था, न पता और दस्तावेज, लेकिन आज वही विक्रेता डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है. उन्होंने भारत की उपलब्धियों को उजागर करते हुए बताया कि 1.4 अरब लोगों के लिए डिजिटल पहचान, हर महीने 20 अरब से अधिक लेनदेन करने वाला यूपीआई भुगतान तंत्र और 50 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य आईडी भारत ने विकसित किए. मैक्रों भावुक होते हुए, बोले भारत से मुझे प्रेम है.

एआई सही इस्तेमाल से मानवता के लिए वरदान

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इंडिया एआई-इम्पैक्ट समिट में कहा कि एआई इंसानी क्षमता को रिप्लेस न करे बल्कि उसका पूरक बने. उन्होंने श्रमिकों में निवेश पर जोर देते हुए कहा कि तकनीक का असली लाभ मानवता को बेहतर बनाना और धरती की रक्षा करना है.गुटेरेस ने समावेशी और जिम्मेदार एआई की आवश्यकता जताई और कहा कि बच्चों के लिए अनियंत्रित एआई परीक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए.

नाइजीरिया और पाकिस्तान में गैस रिसाव से 53 की मौत

नाइजीरिया, 19 फरवरी. उत्तर-मध्य नाइजीरिया के पठार राज्य के वासे क्षेत्र में एक खदान में जहरीली गैस के अचानक रिसाव से कम से कम 37 लोग मारे गए, जबकि 26 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस प्रवक्ता अल्फ्रेड अलाबो ने बताया कि खनिकों को लेड ऑक्साइड और सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसों का सामना करना पड़ा, जो बंद या खराब हवादार जगहों में जानलेवा साबित होती हैं.

मृतकों के शवों को धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार परिवारों को सौंप दिया गया है. नाइजीरिया सरकार ने खनन स्थल को सील कर दिया है और रिसाव के कारणों की जांच जारी है. ठोस खनिज विकास मंत्री डेले अलाके ने बताया कि खनिक खनन के दौरान गैस उत्सर्जन के खतरों से अनजान थे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि खदान कानूनी रूप से संचालित थी या नहीं. देश में अवैध खनन पर नियंत्रण की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में इससे कई लोग मारे जा चुके हैं.

पाकिस्तान के कराची में एक आवासीय अपार्टमेंट में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण विस्फोट हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 16 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए. विस्फोट गुरुवार सुबह करीब 4:30 बजे ओल्ड सोल्जर बाजार इलाके में पहली मंजिल पर हुआ.

एक नजर में

590 करोड़ के अकाउंट और डिपॉजिट कुर्क किए

नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत विंजो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के 590 करोड़ रुपये के बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और बॉड जब्त कर लिये हैं. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) की धारा 4 के उल्लंघन के मद्देनजर की गई है. ईडी के बेंगलुरु कार्यालय ने कहा कि विंजो रियल मनी गेम्स (आरएमजी)/ऑनलाइन जुआ के कारोबार में लगी हुई है और इसके पास 100 से अधिक गेम हैं जिसके लगभग 25 करोड़ उपभोक्ता हैं.

राहुल गांधी को धमकी देने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को दावा किया कि करणी सेना का एक कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 25 अन्य सांसदों के खिलाफ गोली मारने की धमकी दी है.वीडियो वायरल होने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी राज आमेरा को गिरफ्तार कर लिया. पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह धमकी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पूरे आरएसएस-भाजपा तंत्र द्वारा प्रेरित एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है.

42 विधायकों को हाइकोर्ट का नोटिस

पटना , 19 फरवरी. पटना हाईकोर्ट ने चुनावी अनियमितताओं और नॉमिनेशन के हलफनामों में कथित गलत जानकारी के आरोपों पर 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इन विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में हारने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और शपथपत्र में तथ्यों की छिपाने या गलत जानकारी देने के आरोपों के आधार पर याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों को निर्धारित समय में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. नोटिस के बाद अधिकांश विधायकों ने मीडिया से बचते हुए कहा कि वे अपना जवाब अदालत में देंगे. जीवेश मिश्रा ने कहा, 'हाईकोर्ट का जवाब हमलोग हाईकोर्ट में ही देंगे.' वहीं, अन्य विधायकों ने इसे कानूनी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होगा.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर 2025 को घोषित हुए थे, जिसमें एनडीए को बड़ी जीत मिली थी. चुनाव में हारने वाले कुछ उम्मीदवारों ने इस जीत पर प्रश्न उठाते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब अदालत में दाखिल होने वाले जवाब और दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी. इस कार्रवाई से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायपालिका की सक्रियता सामने आई है, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इसकी गंभीरता पर चर्चा हो रही है.

मुफ्त पैसा, खाना और बिजली देंगे तो काम कौन करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं पर कड़ी टिप्पणी की : रोजगार को प्राथमिकता दें

- मुफ्त कल्चर पर सुको ने सरकारों को लगाई फटकार
- सीजेआई ने कहा- विकास के लिए पैसा कहां से आएगा

नई दिल्ली, 19 फरवरी. सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) पर बढ़ते खर्च पर चिंता जताई है और कहा कि सरकारों को केवल मुफ्त चीजें बांटने की बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यों के बढ़ते राजस्व घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि कई राज्य भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त खाना, बिजली, साइकिल जैसी योजनाएं चला रहे हैं. उन्होंने कहा, 'अगर ये फ्रीबीज जारी रहेगी, तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा?' कोर्ट ने कहा कि कैश ट्रांसफर और मुफ्त सुविधाओं की घोषणा वित्तीय दृष्टि से समझदारी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी फटकार लगाई, जिसने कुछ समुदायों के लिए बिजली टैरिफ में सब्सिडी देने की योजना बनाई थी. इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर वित्तीय दबाव पड़ा, और कंपनियों ने कोर्ट में अपील की.

सीजेआई ने कहा कि राज्य को रोजगार सृजन के रास्ते खोलने चाहिए. मुफ्त सुविधाओं से सीधे लोगों के खातों में पैसा भेजने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो राजस्व घाटे में रहने वाले राज्यों के लिए जोखिमपूर्ण है. अदालत ने कहा कि जहां जरूरतमंदों को मदद देना जरूरी है, वहीं जो लोग पहले से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनके खाते में फ्रीबीज पहुंच रहे हैं.

लाभ देने के लिए बजटीय आवंटन में दर्शाएं

न्यायमूर्ति बागची ने सुझाव दिया कि यदि ऐसे लाभ दिए जाने हैं, तो उन्हें बजटीय आवंटन में पारदर्शी रूप से दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने अनियोजित खर्च के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, 'यदि आप वास्तव में यह सब करना चाहते हैं, तो इसे बजटीय आवंटन में डालें और फिर उचित ठहराएं कि आप ऐसा कैसे करेंगे।

देशभर में होगा एसआईआर का सर्वे : ईसी

नई दिल्ली, 19 फरवरी. चुनाव आयोग ने गुरुवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखकर SIR की तैयारियों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. दिल्ली, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने की संभावना है.

SIR का उद्देश्य वोटर सूची को अपडेट करना है. इसमें 18 साल से अधिक उम्र के नए वोटरों को जोड़ा जाता है और मृतक या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं. गलत नाम या पते को सही किया जाता है.

पहले फेज में बिहार में SIR हुआ था, जबकि दूसरे फेज में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से प्रक्रिया जारी है. असम में इसके बजाय स्पेशल रिवीजन 10 फरवरी को पूरा हुआ.

SIR घर-घर जाकर ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) द्वारा किया जाता है. वोटरों को फॉर्म भरकर जानकारी मिलान करनी होती है. यदि किसी का नाम दो जगह है तो कटवाना होगा और यदि नाम सूची में नहीं है तो जोड़वाना होगा. इसके लिए पेंशनर आईडी, पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, NRC/परिवार रजिस्टर के नाम आदि दस्तावेज मान्य हैं.

इस प्रक्रिया का मकसद पिछले 21 साल में वोटर सूची में हुए बदलावों को सुधारना, माइग्रेशन, दोहरी वोटर सूची, मृतक और विदेशी मतदाताओं के नाम हटाना तथा योग्य मतदाताओं को सूची में सुनिश्चित करना है.

एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की नाकाम

जम्मू-कश्मीर, 19 फरवरी. राजौरी जिले में सुरक्षा बलों को दो बड़ी कामयाबी मिली हैं. सेना ने सुंदरबनी क्षेत्र में एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की. 19 फरवरी को खुफिया इनपुट और लगातार निगरानी के आधार पर नथुआ टिब्बा इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी गई. सेना की सतर्क टुकड़ियों ने तुरंत कार्रवाई कर जवाबी फायरिंग की, जिससे आतंकियों की घुसपैठ विफल रही. पूरे क्षेत्र में जवानों को रणनीतिक रूप से तैनात कर हाई लेवल ऑपरेशनल अलर्ट जारी किया गया है. इसी दौरान राजौरी पुलिस ने 54 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संयुक्त अभियान में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया.

ड्रोग पैराशूट का सफल भार परीक्षण

दिल्ली/ चंडीगढ़, 19 फरवरी . रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में 'ड्रैग पैराशूट' का लोड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया. भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

ड्रैग पैराशूट, या 'ड्रोग पैराशूट', चालक दल मॉड्यूल को नीचे उतरते समय स्थिर करने और उसकी गति को कम करने के लिए डिज़ाइन किये गये हैं. ये पैराशूट समुद्र में लैंडिंग से पहले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं. इन्हें गगनयात्रियों को ले जाने वाले भारी और तेज गति से

चलने वाले अंतरिक्ष कैप्सूल की रफ्तार धीमी करने के लिए तैनात किया जाएगा.

इन परीक्षणों के दौरान लोड की स्थितियों की जांच डीआरडीओ की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज डायनेमिक टेस्टिंग सुविधा का उपयोग करके की गयी. इस ट्रायल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, एरियल डिलीवर रिसर्च एडं डेवलपमेंट प्रतिष्ठान (एडीआरडीई) और टर्मिनल बैलेस्टिक रिसर्च लैबोरेट्री (टीबीआरएल) के वैज्ञानिकों की टीमों ने हिस्सा लिया. रक्षा मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परीक्षण उच्च क्षमता वाले रिबन पैराशूट के डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता को सिद्ध करता है.

गर्माई राजनीति | विपक्ष ने सदन में मांगा शुक्ल और विजयवर्गीय का इस्तीफा, सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित

इंदौर के दूषित जल कांड को लेकर सदन में जबर्दस्त हंगामा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 19 फरवरी. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को सदन में जबर्दस्त हंगामा हुआ. विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की. विपक्षी सदस्य अपनी मांगों को लेकर आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए.

मामला ऐसा गरमाया कि सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित करना पड़ा. इस मामले में गतिरोध प्रश्नकाल से शुरू हुआ जो कि अपरान्ह तीन बजे तक चला. आखिरकार अब विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को इस मामले में चर्चा कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर कार्यवाही फिर सामान्य तरीके संचालित हो सकी. हांलाकि इस दौरान मंत्री शुक्ल ने दूषित पानी के सेवन से मरने वालों की संख्या को महज 22 बताया.

प्रश्नकाल में भागीरथपुरा पर सवाल पर आपत्ति: ये मामला प्रश्नकाल के दौरान उठा.

आश्चर्यजनक रूप से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इस संबंध में सवाल तारांकित के 25 सवालों में शामिल किया गया था. 25 सवालों में से सवाल का क्रम 7वां था. तारांकित में ये सवाल को शामिल किए जाने पर सबसे पहले तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नियमों का हवाला देते हुए आपत्ति जाहिर की और कहा कि मामला न्यायिक है, इसलिए सदन में इस पर सवाल को शामिल नहीं किया जाना था, वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने भी इस पर सवाल पर ऐतराज जताया. मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सदन में चर्चा कराने का आश्वासन दिया था, इसलिए ही उन्होंने विशेष परिस्थिति में प्रश्न को शामिल करने की अनुमति दी है. प्रश्न के लिखित जवाब में पहले तो उप मुख्यमंत्री ने 20 लोगों की मौत होने और 2 लोगों के उपचाररत होने के साथ ही बताया कि 459 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने स्टूल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मौत कालरा और ई-कोली से भी हुई. उन्होंने कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट के इंदौर बैंच के रिटायर्ड जस्टिस से कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है.

(शेष पेज 2 पर)

अनिल अंबानी ने कहा- भारत नहीं छोड़ूंगा, जांच में करूंगा सहयोग

नई दिल्ली, 19 फरवरी. अनिल अंबानी ने 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने वचन दिया कि वे अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे. यह कदम उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के बीच आया है.

हलफनामे में अंबानी ने भरोसा दिलाया कि वे ईडी और सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे. इस हलफनामे से पहले, उनके सीनियर वकील मुकुल

रोहतगी ने 4 फरवरी को मौखिक रूप से अदालत को आश्वस्त किया था कि अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे. अब यह कानूनी रूप से लिखित रूप में जरूरी हो गया है. ईडी की जांच में सामने आया कि रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस में 2017-19 के बीच बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ.